

कोरोना को हराने के लिए हर स्तर पर  
बेहतर कार्य करने की आवश्यकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों/श्रमिकों के लिए स्थापित  
क्वारेन्टीन सेन्टर, आश्रय स्थलों तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं में  
जिलाधिकारी को सहयोग करने के लिए 75 जनपदों में आई०ए०एस०  
तथा वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए

भारत सरकार की एडवायजरी के अनुरूप सुरक्षा के  
सभी मानक अपनाते हुए उद्योग धन्धों को शुरू कराया जाए

कम्युनिटी किचन पहले से ही जियो टैग, इसी क्रम में  
क्वारेन्टीन सेन्टर को भी जियो टैग किया जाए

यह सुनिश्चित किया जाए कि हॉट स्पॉट में  
रहने वाले कर्मी अपने कार्य स्थल पर न आयें,

लोग अनिवार्य रूप से मास्क अथवा फेस कवर आदि पहन कर ही बाहर निकलें

बच्चों के टीकाकरण कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए,  
यह भी ध्यान रखा जाए कि इस कार्य से जुड़ा पैरामेडिकल स्टाफ  
मास्क, ग्लव्स व सेनिटाइजर का उपयोग करे

सभी वेंटीलेटर फंक्शनल रखे जाएं

मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों तथा पार्षदों से संवाद स्थापित  
कर निगरानी समितियों के द्वारा यह सुनिश्चित कराएं कि किसी भी बाहरी  
व्यक्ति के चोरी-छिपे उनके क्षेत्र में आने पर वे प्रशासन को सूचित करें

कोविड-19 से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिगत राजस्व वृद्धि  
के वैकल्पिक स्रोत चिन्हित करने के लिए कार्ययोजना बनायी जाए

राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना से अधिकाधिक  
लोगों को जागरुक कर उन्हें लाभान्वित किया जाए

प्रवासी कामगारों तथा श्रमिकों को एक जनपद-एक उत्पाद योजना,  
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा दुग्ध समितियों से जोड़ा जाए

लखनऊ : 04 मई, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश  
वापस आ रहे प्रवासी कामगारों/श्रमिकों के लिए स्थापित क्वारेन्टीन सेन्टर,  
आश्रय स्थलों तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं में सम्बन्धित जिलाधिकारी

को सहयोग प्रदान करने के लिए सभी 75 जनपदों में आई0ए0एस0 तथा वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। यह अधिकारी सम्बन्धित मण्डलायुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे। इस कार्य के लिए उन्होंने ऐसे अधिकारियों को ही नामित किए जाने के निर्देश दिए जो किसी भी प्रकार से कोविड-19 के नियन्त्रण आदि कार्यों से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हर स्तर पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटने वाले प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को क्वारंटीन सेन्टर भेजते हुए वहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम गठित की जाएं। यह मेडिकल टीम हेल्थ चेकअप तथा स्क्रीनिंग का कार्य करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्वारंटीन सेन्टर तथा शेल्टर होम में लोगों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अलग-अलग अधिकारियों द्वारा क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया जाए। इनमें साफ-सफाई तथा सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन पहले से ही जियो टैग हो चुके हैं। इसी क्रम में क्वारंटीन सेन्टर को भी जियो टैग किया जाए। इसका लाभ यह होगा कि राहत कंट्रोल रूम की वीडियो वॉल से क्वारंटीन सेन्टर की लोकेशन तथा वहां पर संचालित कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेल्थ चेकअप में स्वस्थ पाये गये लोगों को 14 दिन की होम क्वारंटीन के लिए घर भेजते समय राशन किट उपलब्ध कराया जाए। निराश्रित व्यक्तियों को राशन किट के साथ 01-01 हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाए। अस्वस्थ लोगों के उपचार की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों तथा नगरों के पार्षदों से

संवाद स्थापित करते हुए निगरानी समितियों के द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि चोरी-छिपे उनके क्षेत्र में आए तो वे प्रशासन को सूचित करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हॉट स्पॉट में रहने वाले कर्मों अपने कार्य स्थल पर न आयें, क्योंकि ऐसे लोगों की कोरोना कैरियर बनने की सम्भावना रहती है। इसका भी ध्यान रखा जाए कि लोग अनिवार्य रूप से मास्क अथवा फेस कवर आदि पहन कर ही बाहर निकलें। बच्चों के टीकाकरण कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि इस कार्य से जुड़ा पैरामेडिकल स्टाफ मास्क, ग्लव्स व सेनिटाइजर का उपयोग करे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को तेजी से प्रशिक्षित किया जाए। इमरजेन्सी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली राजकीय एवं निजी नॉन-कोविड अस्पतालों की सूची संकलित की जाए। पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देते हुए टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि की जाए। सभी वेंटीलेटर फंक्शनल रखे जाएं। आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद आदि जनपदों में विशेष निगरानी की आवश्यकता है। इन जनपदों से प्रभावी संवाद बनाकर यहां की समस्याओं का निराकरण कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने लेबर रिफॉर्म पर तत्काल कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बैंक खाता संख्या व आधार कार्ड संख्या को संकलित करने की कार्यवाही को जारी रखते हुए लाभार्थियों के खाते में भरण-पोषण भत्ते की धनराशि अन्तरित की जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में चीनी मिलें तथा ईट-भट्ठा उद्योग अच्छी प्रकार संचालित हुआ। भारत सरकार की एडवायजरी के अनुरूप सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाते हुए उद्योग धन्धों को शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक वृहद एवं व्यावहारिक

कार्य योजना बनायी जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार सेक्टरल नीतियों में संशोधन पर भी विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 से आर्थिक गतिविधियों प्रभावित हुई हैं। इसलिए राजस्व वृद्धि के वैकल्पिक स्रोत चिन्हित करने के लिए कार्ययोजना बनायी जाए। प्रवासी कामगारों तथा श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इन्हें एक जनपद-एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा दुग्ध समितियों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना से प्रदेश के जुड़ जाने से यहां रह रहे महाराष्ट्र के मूल निवासियों ने खाद्यान्न प्राप्त किया है। इसी प्रकार गोवा और कर्नाटक राज्यों में प्रदेश के मूल निवासियों ने इस योजना का लाभ उठाकर वहां खाद्यान्न प्राप्त किया। उन्होंने इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरुक करने के निर्देश दिए, ताकि वे इसका लाभ ले सकें।

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवरथी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी0 अवरथी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल एवं श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव खाद एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।